महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – उनहत्तरवां संस्करण (माह सितंबर, 2021)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. अब प्रदेश में डाइनिंग टेबल पर परोसा जाएगा मध्यान्ह भोजन
3. "Spatial Planing for Block/Model Cluster Panchayat Development for the State of Madhya Pradesh विषय पर तीन दिवसीय वेबिनार का आयोजन
4. श्रीमती आरती वर्मा ने ईंट निर्माण आर्थिक गतिविधि से किया अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम
5. लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति–भारत और अफगानिस्तान
6. ''कोविड–19 की रोकथाम में पंचायत की भूमिका'' विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन
7. स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का हीरक जयंती कार्यक्रम
8. आत्मनिर्भरता के कदम
9. कोरोना वालेंटियर अभियान अंतर्गत सराहनीय कार्य
10. लाखों की कमाई कर रहे, देवगढ़ के कृषक
11. जेन्डर (मानसिकता है क्योकि)
12. कोविड–19 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग
13. ''सच हुआ सपना, अपने आशियाने का''
14. समूह ने संभाली गेहूं उपार्जन की कमान
15. ''कोविड–19 से बचाव हेतु समूह का अभिनव प्रयास''
16. ''कपिलधारा'' से आर्थिक समृद्धी कि ओर

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री उमाकांत उमराव (IAS)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का उनहत्तरवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2021 का नौवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयो में छात्र/छात्राओं को अब मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) फर्श या मैट पर बैठकर नहीं करना होगा। अब उनके लिए शासकीय विद्यालयो में डाइनिंग टेबल बनाए जाएगें, जहां वह बैठकर आराम से मध्यान भोजन कर सकेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी द्वारा इस योजना की शुरूआत 8 सितंबर को की गई इस समाचार आलेख को ''अब प्रदेश में डाइनिंग टेबल पर परोसा जाएगा मध्यान्ह भोजन'' के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण गतिविधियों **''Spatial Planing for Block/Model Cluster Panchayat Development for the State of Madhya Pradesh विषय पर तीन दिवसीय वेबिनार का आयोजन'', ''कोविड–19 की रोकथाम में पंचायत की भूमिका'' विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन''** तथा **'' स्वतंत्रता दिवस पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ का हीरक जयंती कार्यक्रम सम्पन्न''** को समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ **''श्रीमती आरती वर्मा ने ईंट निर्माण आर्थिक गतिविधि से किया अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम'', ''लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति – भारत और अफगानिस्तान'', ''आत्मनिर्भरता के कदम'', ''कोरोना वालेंटियर अभियान अंतर्गत गठित समितियां कर रही सराहनीय कार्य'', ''नन्दन फलोद्यान से लाखों की कमाई कर रहे, देवगढ़ के कृषक'', ''काव्य रचना – जेन्डर (मानसिकता है क्योकि)'', ''कोविड–19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग'', ''प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से सच हुआ सपना, अपने आशियाने का'', ''समूह ने संभाली गेहूं उपार्जन की कमान'', ''कोविड–19 से बचाव हेतु देवकृपा समूह का अभिनव प्रयास''** एवं **''कपिलधारा से आर्थिक समृद्धी कि ओर''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

अब प्रदेश में डाइनिंग टेबल पर परोसा जाएगा मध्यान्ह भोजन

मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयो में छात्र/छात्राओं को अब मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) फर्श या मैट पर बैठकर नहीं करना होगा। अब उनके लिए शासकीय विद्यालयो में डाइनिंग टेबल बनाए जाएगें, जहां वह बैठकर आराम से मध्यान भोजन कर सकेंगे। इसके अलावा अब प्लेट लेकर लाइन में लगे रहने की जरूरत भी नहीं होगी और सर्विस के तरीके को भी बदला जाएगा।

डाइनिंग टेबल पर शासकीय विद्यालयो के बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने की योजना की शुरूआत मध्यप्रदेश के गुना जिले से होगी। जिले के 80 पंचायत के 100 सरकारी स्कूलों में इस योजना को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी द्वारा इस योजना की शुरूआत 8 सितंबर को की गई। इस योजना की शुरूआत करते हुए माननीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्र मैट या फर्श पर बैठकर भोजन करते थे, पर अब मनरेगा के तहत सीमेंट के बेंच और टेबल बनाए जा रहे हैं. इसके साइज स्कूल के टेबल्स से दोगुनी होगी।

अब तक 20 स्कूलों में डाइनिंग टेबल बनाने का काम हो चुका है। इसके अलावा छात्रों को भी टेबल पर खाने का तरीका बताया जाएगा। इस स्कीम को पूरे राज्य के सभी पंचायतों में लागू किया जाएगा।

"Spatial Planing for Block/Model Cluster Panchayat Development for the State of Madhya Pradesh विषय पर तीन दिवसीय वेबिनार का आयोजन

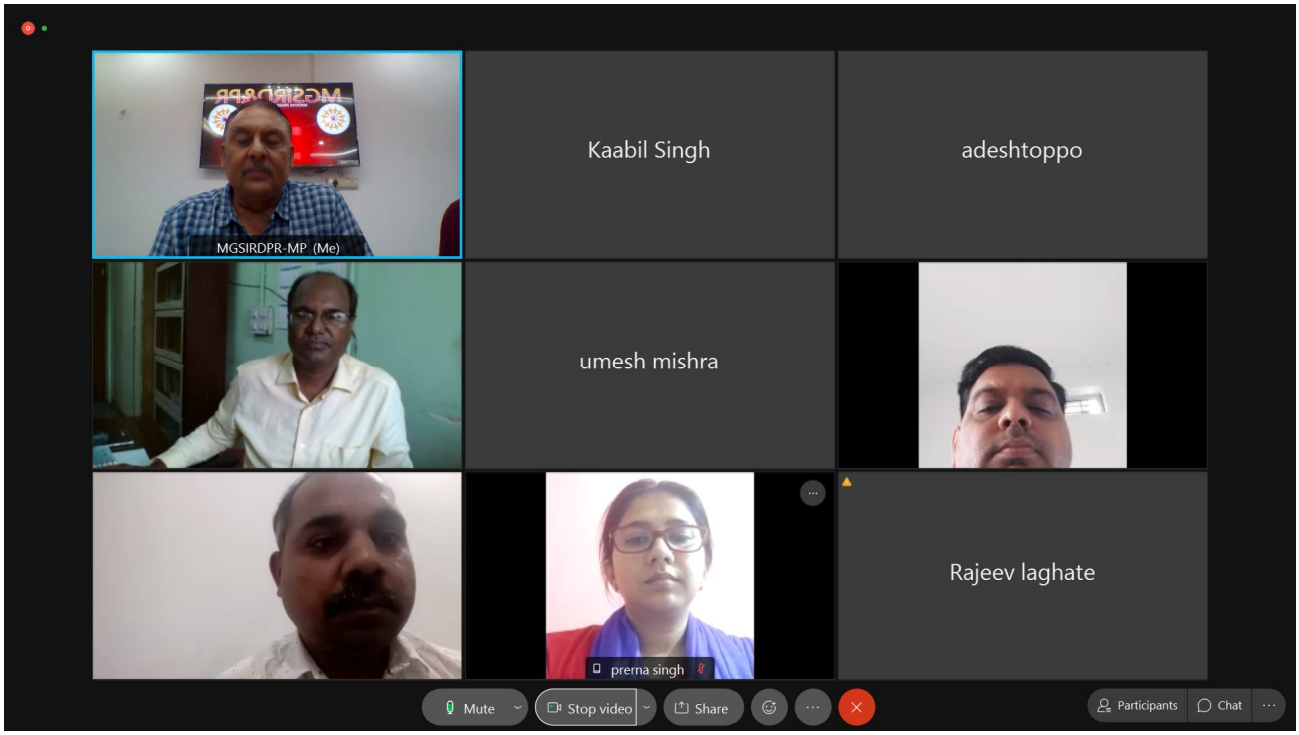

"Spatial Planing for Block/Model Cluster Panchayat Development for the State of Madhya Pradesh" विषय पर संस्थान एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारी/संकाय सदस्य तथा प्रोग्रामर के साथ–साथ जिला पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण 3 दिवसीय वेबिनार दिनांक 01 से 03 सितंबर 2021 अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण वकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद अंर्तगत Centre for Geo-informatics Applications in Rural Development (CGARD) के सहयोग से महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर द्वारा आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के उद्देश्य

क) ब्लॉक/क्लस्टर पंचायत विकास में स्थानिक योजना के संदर्भ और महत्व के बारे में सदस्यों के बीच समझ विकसित करना।

बी) बीडीपी के संदर्भ में स्थानिक योजना की कार्यप्रणाली के बारे में उनकी समझ विकसित करना।

सी) भू–सूचना विज्ञान (जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस सिस्टम) और स्थानिक योजना की अवधारणा।

घ) ग्राम मानचित्र और भुवन पंचायत पोर्टलों का उपयोग करके ब्लॉक/क्लस्टर विकास योजना के लिए जीआईएस डेटा के विश्लेषण पर कार्य कौशल विकसित करना।

बीडीपी और डीपीडीपी की तैयारी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भी आवश्यक है कि, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतें एफएफसी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जो कि योजनाओं के लिए उनके रिसोर्स एनवलप का हिस्सा भी हैं। ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी का विषय गुणात्मक तरीके से बड़ी संख्या में ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए बिल्कुल नया हो सकता है। सतत विकास के लिए भौगोलिक डेटा के उपयोग के साथ ब्लॉक स्तर पर प्रासंगिक डेटा प्राप्त करके और योजना बनाकर

योजना प्रक्रिया में निष्पक्षता रखने की आवश्यकता है। यह उपयोगकर्ता को भौगोलिक डेटा के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद, कोर्स डायरेक्टर द्वारा इस प्रशिक्षण की भूमिका एवं उपयोगिता को बताया गया। साथ ही श्री दिलीप कुमार पॉल, लीड कंसल्टेंट, डॉ. पी. केशव राव, हेड सीगार्ड, डॉ. एम.व्ही. रविबाबू, एसोसियेट प्रोफेसर, तथा संस्थान की ओर से श्रीमती सुनीता चौबे, उप संचालक (प्रशिक्षण), श्री एस.के. सचान, उपसंचालक (समन्वय), डॉ. अश्विनी अंबर, उप संचालक (प्रशासन) तथा प्रशिक्षण के लोकल कोर्स कॉर्डीनेटर श्री जय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री आशीष कुमार दुबे भी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में संस्थान एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रदेश की जिला पंचायतों के कुल 129 प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई।

प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित फीडबैक एवं सुझाव दिये गये, सभी का धन्यवाद देते हुये प्रशिक्षण का समापन किया गया।

आशीष कुमार दुबे
प्रोग्रामर

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर द्वारा ध्वजारोहण किया गया, इस अवसर पर सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्रीमती आरती वर्मा ने ईंट निर्माण आर्थिक गतिविधि से किया अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम

पारिवारिक स्थिति

मध्यप्रदेश के बैतूल के विकासखण्ड शाहपुर के ग्राम सोहागपुरढाना निवासी श्रीमती आरती वर्मा ने बी. काम तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आरती का विवाह खेती–किसानी करने वाले परिवार के श्री संदीप के साथ हुआ। खेती–किसानी की साधारण आमदनी से इनके परिवार की आर्थिक आवश्यकताऐं अच्छे से पूरी नहीं हो पाती थीं। घर–गृहस्थी के काम–काज में आरती उलझते गई।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ाव

कुछ समय निकल जाने के बाद इनके सामने स्वयं आगे बढ़ाने और अपने पारिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने सवाल खड़ा हुआ था। ऐसी परेशानी के चलते आरती का सम्पर्क मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के सहयोगियों से हुआ। इन्होंने अपनी परेशानी आजीविका मिशन के सहयोगी दल के सदस्यों को बताई। आजीविका मिशन के सहयोगी दल के सदस्यों द्वारा इन्हें स्व–सहायता समूह में शामिल होने की सलाह दी गई।

स्व–सहायता समूह से जुड़ाव

आरती ने अपने ग्राम सोहागपुरढ़ाना में वर्ष संचालित रानी आजीविका स्व–सहायता समूह की दीदियों से मिल कर चर्चा की। वर्ष 2017 में आरती आजीविका मिशन के अन्तर्गत ''रानी आजीविका स्व सहायता समूह'' से जुड़ गई। वे समूह की बैठकों में सक्रिय भागीदारी करती। समूह में नियमित रूप से बचत की राशि जमा करतीं।

आरती की आवश्यकता को देखते हुये समूह में यह किया गया कि आर्थिक गतिविधि को चलाने के लिये ऋण दिया जावे। आरती को यह सब सपना जैसा लग रहा था। समूह के सहयोग से आरती अब दो बार में ऋण के रूप में राशि 40 हजार रूपये प्राप्त कर लिये।

ईंट निर्माण गतिविधि बना आजीविका का साधन

म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ईंट निर्माण का कार्य हाथ में लेकर आरती ने अपने परिवार के लिये आमदनी का जरिया बना लिया। ईंट तो बन गई थीं किन्तु इन्हें कहां बेचा जावे ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये सवाल लेकर वे ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के पास गई। ग्राम पंचायत में विचार–विमर्श के बाद आरती को बताया गया कि वे ईंटों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण के लिए सप्लाई कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन से आरती को अब तो सारी मुश्किलें आसान लगने लगी और अपने सपने भी पूरे होते नजर आ रहे थे। आरती अपने परिवार के साथ मिल कर ईंट निर्माण कर ईंटों की सप्लाई प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को करती हैं। हॉ, इससे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को अपने समीप से ईंटें मिलने लगीं जिससे हितग्राहियों को कम परिवहन व्यय हुआ जिससे कम लागत राशि में आवास निर्मित हुये। वर्तमान में आरती ईंट निर्माण से प्रतिमाह 10 से 12 हजार रूपए की आमदनी हो रही है।

ईंट निर्माण गतिविधि से जो आमदनी हो रही थी आरती के लिये वह नाकाफी लगी। वह सोचने लगी कि इस व्यवसाय को आगे और कैसे बढ़ाया जावे। इसके लिए आरती ने अपने अपने स्व–सहायता समूह, ग्राम संगठन और ग्राम पंचायत से चर्चा की। अब तक समूह से ऋण के रूप में लिये 40 हजार रूपये की ऋण वापसी आरती ने कर दिया था। आजीविका मिशन के ग्राम संगठन के माध्यम से आरती को राशि 50 हजार ऋण के रूप में मिल गये। इस प्रकार से ईंट निर्माण की गतिविधि से अच्छी खासी आमदनी आरती को होने लगी। जनता कर्फ्यू के दौरान आरती द्वारा सरकारी कार्यों (प्रधानमंत्री आवास योजना) में तैयार ईंट सप्लाई की जा रही है, जिससे कोविड–19 महामारी के फेस–2 में परिवार का जीवनयापन हो रहा है।

कोविड़–19 से बचाव के लिए जागरूकता कार्य

स्व सहायता समूह से जुड़ी श्रीमती वर्मा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्रामीणों में जागरूकता लाने का कार्य भी कर रही हैं। अप्रैल 2021 से पूरे प्रदेश में कोविड–19 महामारी के फेस–2 के कारण जिले में भी संक्रमण का अत्यधिक प्रसार होने लगा, जिसके कारण शासन द्वारा जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। आरती वर्मा के द्वारा ग्राम के अन्य स्व सहायता समूहों की महिलाओं एवं ग्रामवासियों को कोविड के प्रति जागरूक करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं अपने–अपने घरों में ही रहने के बारे में बताया जा रहा था।

शासन की योजनायें का सहयोग

आरती कहती हैं कि अगर शासन की आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम नहीं होती तो वे अपने परिवार का विकास कभी भी नहीं कर सकती थी। वे बहुत खुश हैं और बताती हैं मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, ग्राम पंचायत, ग्राम संगठन और अपने स्व–सहायता समूह की मदद से ही आज अपने ईंट निर्माण गतिविधि को स्थापित कर सकीं हैं और सफलतापूर्वक संचालित भी कर रहीं हैं। इस सफलता का श्रेय शासन की योजनाओं को देतीं हैं।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति – भारत और अफगानिस्तान

भारत सरकार की महिला केबिनेट मिनिस्टर

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है, इसमें समय–समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है. यदि हम महिलाओं की स्थिति का आंकलन करें तो पता चलेगा कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिती में अनेक तरह के उतार–चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है. इन बदलावों का ही परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों–दिन बढ़ रहा है जो कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है।

21 वीं सदी शुरुआत से महिलाओं की रही है. इन सालों में महिलाओं का भारत की आर्थिक व्यस्था में योगदान बढ़ा है इसका ही परिणाम है कि आज भारत कि महिलाएं राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुँच कर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत विश्व में भारत की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है. आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाऐं डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं स्वतंत्रता के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं. भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाऐं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट और उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाँ वर्षों पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां सिर्फ़ महिलाओं ने स्वयं को स्थापित ही नहीं किया है बल्कि वहां सफल भी हो रहीं हैं।

महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये जो सुधार आन्दोलन शुरू हुआ उससे समाज में एक नयी जागरूकता पैदा हुई है। बाल–विवाह, भ्रूण–हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का का काफ़ी प्रयास हुआ है. शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गाँधी जी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है. शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

सक्रिय होने में बहुत मदद मिली. महिलाए अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी हैं। आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है। वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं इससे स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं।

लोकतंत्र के पतन का दुष्परिणाम महिलाओं पर कैसे पड़ता है। इसका ज्वलंत उदाहरण अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था, जब ये देश भी फैशन, रोजगार और करियर के मामले में काफी आगे था लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं, जब महिलाएं भी अपना करियर बना सकती थी। सब कानून व्यवस्था के मुताबिक चलता था. सरकार विकास कार्यों को करने में सक्षम थी और हर किसी को आजादी थी। अफगान महिलाओं को पहली बार 1919 में मतदान करने की आजादी मिली. यानी ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिए जाने के एक साल बाद और एक साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी गई थी। 1960 के दशक में पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही एक नया संविधान राजनीतिक भागीदारी सहित जीवन के कई क्षेत्रों में समानता लाया.लेकिन 1970 के दशक में तख्तापलट और सोवियत कब्जे के दौरान 80 और 90 के दशक में मुजाहिदीन समूहों और सरकारी बलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया. फिर तालिबान का आतंक स्थापित हुआ और अफगानिस्तान में महिलाओं से उनके अधिकार तेजी से छीन लिए गए। तालिबान ने महिलाओं के लिए मानवाधिकारों तक को खत्म कर दिया. हर तरफ इनके साथ भेदभाव शुरू हुआ. यहां लड़की के रूप में पैदा होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया। तालिबान ने इस्लामी शरिया कानून को लागू किया और महिलाओं और लड़कियों के लिए नए नियम लागू हुए जैसे– स्कूल जाने और पढ़ाई करने पर रोक लगाई गई, नौकरी करने पर रोक, बिना पुरुष साथी के घर से निकलने पर रोक, सार्वजनिक स्थान पर शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाने पर रोक, पुरुष डॉक्टर से इलाज कराने पर प्रतिबंध. महिलाओं को काम करने से मना किया गया था तो ऐसे में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा मिलना भी नामुमकिन हो गया.महिलाएं ना तो राजनीति में शामिल हो सकती थीं और ना ही सार्वजनिक रूप से बोल सकती थीं. तालिबान के खात्मे के बाद बीते 20 साल में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी लेकिन अब वो एक बार फिर उन पुराने अंधेरे भरे दिनों की ओर जाने को मजबूर हैं। कब्जे वाले इलाकों में ही जबरन लड़ाकों की शादी महिलाओं से कराई जा रही है. महिलाओं के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वह केवल पुरुष साथी के साथ ही घर से बाहर निकल सकती हैं। उनके लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और पढ़ाई–लिखाई पर रोक लग गई है। आज की महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर डर है तलाकशुदा महिलाओं के लिए स्थिति और भी भयंकर है क्योंकि इनके लिए एक रुढिवादी समाज में कोई स्थान ही नहीं है. दोबारा लोकतंत्र की स्थापना ही अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को लौटा सकती है।

आज के परिपेक्ष्य में भारत और अफगानिस्तान की तुलना करने से यह सार निकलता है कि चूंकि भारत मे लोकतंत्र की स्थापना है इसलिए भारतीय महिलाए अन्य कट्टरपंथी देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र है, और हमे अपने लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए एकजुटता बनाये रखना होगा।

माधुरी शर्मा,
उपसंचालक

''कोविड–19 की रोकथाम में पंचायत की भूमिका'' विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन

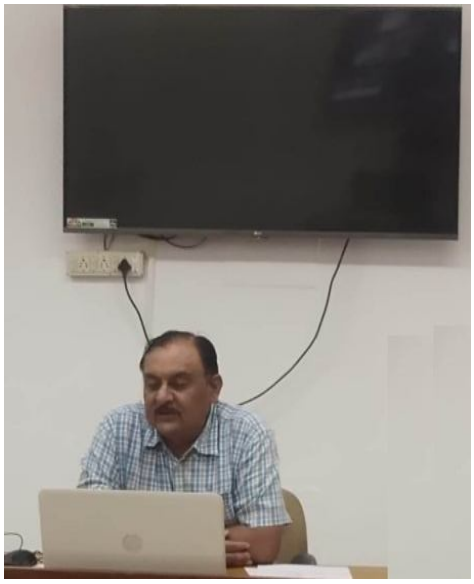

वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी चलते संस्थागत फेस–टू–फेस प्रशिक्षण न होने के कारण से ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया है। उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण के सफलता पूर्वक पूर्ण करने हेतु महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर में कार्यरत अधिकारी, संकाय सदस्यों के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु कोविड–19 की रोकथाम पंचायत की भूमिका विषय पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 02 अगस्त 2021 को किया गया। आयोजित एक दिसवीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रारंभ में संस्थान के संचालक, श्री संजय कुमार सराफ एवं उपसंचालक श्री शैलेन्द्र कुमार सचान द्वारा प्रशिक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कोविड–19 की रोकथाम में पंचायत की भूमिका के विषय पर आवश्यकता एवं महत्व पर मार्गदर्शन देते हुये सभी प्रतिभागियों को प्रेरित किया।

इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले चार जनपद पंचायत के कुल 140 प्रतिभागी शामिल हुये, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान, सचिव, सीआरपी, स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आदि ऑनलाइन प्रशिक्षण में शामिल हुये। उक्त प्रशिक्षण में ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों के नामांकन से लेकर प्रशिक्षण के अंत में फीडबैक तक की प्रक्रिया के लिए कोविड–19 की रोकथाम पंचायत की भूमिका में विभिन्न विषय जैसे वर्तमान परिदृश्य में कोविड–19 क्या है अंतर्गत विभिन्न प्रकार की महामारियां, कोविड–19 के दुष्प्रभाव, कोविड'–19 के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका/चुनौतियां, जन प्रतिनिधियों की भूमिका, कोविड–19 की सावधानियां, कोविड–19 की जॉच, स्वच्छता और साफ–सफाई, सोशल मीडिया प्लेट फार्म का उपयोग, कोविड–19 के दौर में पंचायत स्तर पर खाद्य सुरक्षा, कोविड–19 के संक्रमण/बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन के आवश्यक दिशा निर्देश, वेक्सीनेशन महाभियान, कोविड–19 प्रोटोकॉल एवं कोविड–19 उपयुक्त, कोविड–19 के रोकथाम के उपाय, उच्च जोखिम समूहों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता के आधार पर कोविड–19 टीकाकरण, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत स्तरीय/आपदा प्रबंधन समितियों की भूमिका एवं दायित्व, कोविड–19 में जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत स्तरीय/आपदा प्रबंधन समितियों की भूमिका एवं दायित्व से संबंधित व्याख्यान एवं चित्र के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण ा के अंत में विषय से संबंधित प्रश्नों का समाधान संकाय सदस्यों द्वारा किया गया।

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर के उपसंचालक महोदय श्री शैलेन्द्र कुमार सचान जी, सत्र समन्वयक श्री सज्जन सिंह चौहान तथा संस्थान के संकाय सदस्यों एवं प्रोग्रामर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ऑनलाइन प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का आभार एवं धन्यवाद देते हुये प्रशिक्षण का समापन किया गया।

सज्जन सिंह चौहान,
संकाय सदस्य

स्वतंत्रता दिवस पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ का हीरक जयंती कार्यक्रम सम्पन्न

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी की 75 वी वर्षगांठ का हीरक जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया संस्थान के संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर द्वारा ध्वजारोहण किया गया ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आई.ए.एस. सेवानिवृत्त कमिश्नर व मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव तथा आनंद विभाग के निदेशक श्री मनोहर दुबे थे, इस अवसर पर श्री दुबे जी ने समय बैंक बनाने तथा इसके माध्यम से असहाय एवं जरूरत मद व्यक्तियों की सहायता का कार्यक्रम प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि कोरोना काल में यह महसूस किया गया कि व्यक्ति के पास धन दौलत, पैसा सब कुछ होने के बाद भी वह इतना लाचार हो गया था कि स्वयं जाकर या उठकर कोई कार्य नहीं कर सकता था । उस समय किसी सहयोगी की आवश्यता महसूस हुई इसी आवश्यकता के अनुरूप श्री मनोहर दुबे जी ने पहल करते हुए गूगल के माध्यम से एक एप का निर्माण किया जिसमें सहयोग करने वाला एवं सहायता प्राप्त करने वाला दोनों उस एप के माध्यम से पंजीयन कराते हैं तो मद्द मांगने पर मदद करने वाले समूह के पास एक मैसेज जाता है और अगर वह मद्द करने के लिये उपलब्ध हो तो उसके द्वारा ओ.के. करने पर यह मैसेज समूह के अन्य सदस्यों के पास से विलोपित हो जाता है। इस प्रकार सहायता मांगने वाले व्यक्ति को त्वरित सहायता प्राप्त हो जाती है।

अतः श्री मनोहर दुबे जी के द्वारा तैयार की गई समय बैंक की अवधारणा मद्दगार व सराहनीय है, उन्होनें इस अवसर पर अपील करी की सभी व्यक्ति प्ले स्टोर पर जाकर ITIMBA नाम से नारंगी कलर की एप को डाउनलोड कर समाज सेवा का कार्य करना चाहिए ।

कार्यक्रम में बैंक के सेवानिवृत अधिकारी व लेखक श्री सुरेश उपाध्याय ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि इतिहास बदला नहीं जा सकता हमकों अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए उन्होंने कहॉ कि जो सपना हमारे क्रांतिकारी साथियों ने देखा है उनके सपनों को हम अवश्य पूरा करेगें ।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक श्री विकास दवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति राष्ट्रीय दिवस के दिन पहनने वालों कपड़ों पर छिड़कने वाला इत्र नहीं है बल्कि राष्ट्र भक्ति तो हमारे शरीर की धमनियों में दौड़ने वाला रक्त है।

कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए एक राष्ट्रभक्ती गीत प्रस्तुत किया गया इस अवसर पर उज्जैन के श्री शम्भू बिलावल द्वारा एकार्डियन और श्री राजेन्द्र कांठेड ने देशभक्ति का गीत सुनाया ।

तल्लीन बड़जात्या
संकाय सदस्य

आत्मनिर्भरता के कदम

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 16 आजीविका स्व सहायता समूहों ने पड़त भूमि को उपजाऊ जमीन में बदलकर अपने जीवन स्तर में लाया परिवर्तन।

जिला बालाघाट के जनपद पंचायत कंटगी के ग्राम जमुनिया के 16 आजीविका स्व सहायता समूहों की 160 दीदीयों ने पड़त भूमि को उपजाऊ जमीन में बदल कर हल्दी खेती प्रारम्भ की डेढ़ एकड़ पड़त भूमि की खेती करने लायक बनाया गया एवं भूमि में वायगांव हल्दी की खेती को इसलिये चुना गया क्यों हल्दी से दोहरा लाभ मिल सकें।

ग्राम जमुनिया समूह की अध्यक्ष श्रीमती पंचेश्वरी मर्सकोले की डेढ़ एकड जमीन सालों से पडत थी, इसे खेती करने लायक बनाया गया और हल्दी की खेती प्रारम्भ की, हल्दी छः माह में तैयार हो जाती है, हल्दी निकलने पर इसे प्लांट के माध्यम से तेल निकाला जाता है और हल्दी बेच जायेगी 20 किलोग्राम में एक लीटर तेल है। बाजार में तायगांव हल्दी की कीमत 90/– प्रति किलो एवं तेल 800/– प्रति लीटर बिकता है।

अभी पांच किंटल हल्दी खेत में लगी है जिसके निकलने पर महिलाओं की आय में वृद्धि होगी एवं खेती को मुनाफा का धंधा बनाने में यह राह अच्छी है निश्चित ही जमुनिया के स्व सहायता समूहों की दीदीयों से सीख लेकर हर समूह को पड़त भूमि उपजाऊ बनाकर खेती करना चाहिये जिससे परिवार की आजीविका वृद्धि हो इस प्रकार महिलाओं के आगे आने पर जेंडर असामनता भी समाप्त होती है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं को समूहों में शामिल कर गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं के आजीविका में वृद्धि करना सराहनीय प्रयास है।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

कोरोना वालेंटियर अभियान अंतर्गत गठित समितियां कर रही सराहनीय कार्य

राजगढ़ जिले के विकासखंण्ड नरसिंहगढ़ के ग्राम महुआ में शादी समारोह में ईटीसी भोपाल से सर्टिफाईड मास्टर रिसोर्स पर्सन एवं वॉलेंटियर मनीष पंचोली द्वारा सभी मेहमानों एवं ग्रामीणों को मास्क वितरित किए गए साथ ही ग्राम प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष विक्रम लववंशी एवं उनके सहयोगियों के द्वारा ग्रामवासियों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया गया।

ईसी प्रकार नगर कुरावर में नगर समिति के अध्यक्ष श्री सुनील राज सहित समिति के सभी पदाधिकारियों द्वारा नगर के सभी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर दो गज की दूरी का पालन करवाया गया साथ ही नगरवासियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। सभी लोग आम नागरिकों को जागरूक करने एवं लोगों की हरसंभव सहायता करने में जुटे हैं।

विकासखंण्ड खिलचीपुर में विकासखंण्ड समन्वयक द्वारा कोरोना वॉलेंटियर में पंजीकृत सभी सदस्यों को 23 अप्रैल को गूगल मीट पर प्रशिक्षित किया गया। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा ग्राम मनीपुरा में बाहरी लोगों को प्रवेश निषेध का संकल्प दिलाया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खिलचीपुर के निर्देशानुसार घर–घर जाकर जनता कर्फ्यू के समर्थन हेतु शपथ पत्र भरवाए गए जिसमें सभी लोगों ने सहयोग किया।

विकासखंण्ड व्यावरा के ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी में वॉलिंटियर मोहन सिंह गुर्जर एवं ग्राम प्रस्फुटन समिति द्वारा टीकाकरण अभियान में लोगों को जागरूक कर टीका लगवाने हेतु प्रेरित किया गया। सभी के प्रयासों से लगभग 50 लोगों को समझा कर टीका लगवाया गया। ग्राम बगवाज के युवाओं द्वारा ग्राम के लोगों को दो गज की दूरी मास्क लगाने के लिए रोको–टोको अभियान चलाया गया।

विकासखंण्ड राजगढ़ में म.प्र. जनअभियान परिषद के समन्वयक मंगल प्रकाश व्यास के मार्गदर्शन में ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों द्वारा अपने–अपने ग्राम की दीवार पर कोरोना जागरूकता हेतु दीवार लेखन कर गांव में जागरूकता लाई गई। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बगा अध्यक्ष हरिओम गुर्जर, देवराज सेन, बीरम सेन, राजाराम गुर्जर आदि द्वारा 18 वर्ष से उपर के लोगों को बैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। इसी कड़ी में गांव के 30 लोगों को टीका लगवाया जा चुका है। तथा लोगों को बार–बार हाथ धोने एवं साफ–सफाई के लिए प्रेरित किया गया।

विकासखंण्ड सारंगपुर में म.प्र. जनअभियान परिषद आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा संचालित प्रस्फुटन समिति एवं नवांकुवर संस्था तथा नगर के सामाजिक संगठनों द्वारा कोरोना महामारी संकट के समय नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आगे आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सारंगपुर अनुभाग अंतर्गत पचोर नगर विकास समिति तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सदस्य, संस्था समाज की नींव का सामाजिक संगठन के सदस्य कोविड–19 के खतरों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिसके कई सदस्य वॉलिंटियर के तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं। संस्था के द्वारा पर्यावरण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पर्यावरण को स्वास्थ्य एवं ईकोसिस्टम को संतुलन बनाये रखने के लिए सभी के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के अनेक प्रयास कर चुके हैं एवं अभी भी जारी हैं।

इस प्रकार जिले की विभिन्न प्रस्फुटन समितियों एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने मानवता की एक उत्कृष्ट मिसाल पेश की है। जिसकी क्षेत्र के समाचार पत्रों में एवं सोशल मीडिया में काफी सराहना हो रही है। जिसने अन्य लोगों में भी निस्वार्थ सहायता करने की प्रेरणा मिलेगी।

आशीष कुमार सोनी,
प्रोग्रामर

नन्दन फलोद्यान से लाखों की कमाई कर रहे, देवगढ़ के कृषक

मोहखेड विकासखण्ड की ग्राम पंचायत देवगढ़ के कृषक, मनरेगा की उपयोजना नन्दन फलोद्यान के तहत संतरें के उद्यान से कर रहे लाखों की कमाई।

जिला मुख्यालय से लगभग 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित देवगढ़ ग्राम पंचायत, जो कि गोंड राजाओं के किले एवं बावलियों को लेकर देश एवं प्रदेश स्तर पर पहचाना जाता है। इसके साथ ही, अब संतरे के बगीचों को लेकर, अपनी अलग पहचान बनाने लगा है। देवगढ ग्राम पंचायत के 59 किसानों को स्वीकृत राशि रू. 76.92 लाख से मनरेगा की नन्दन फलोद्यान उपयोजना से संतरें के बगीचें से लाभान्वित किया गया । किसानों के खेत में गुणवत्तायुक्त पौधें एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय कर, संतरें पौध रोपण का कार्य कराया गया।

पौधा रोपण के प्रति किसानों को प्रोत्साहित कर, लाभ का धंधा बनाने के संबंध में कार्यशालाओं का आयोजन कर, फलों की खेती हेतु कृषकों को प्रेरित किया गया । हितग्राहियों को संतरे पौध रोपण हेतु पौधें एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ ही, अपने बगीचों को विकसित करने हेतु मजदूरी का भुगतान किया गया । जिसके सुखद परिणाम अब

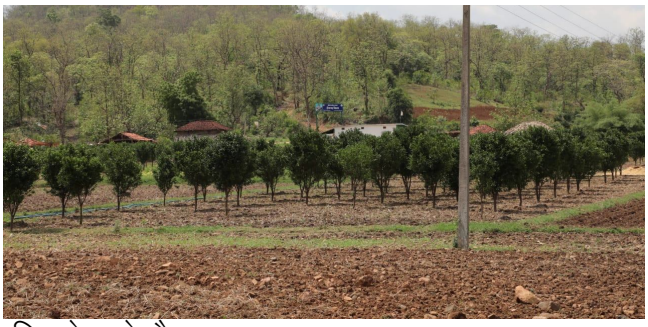

दिखने लगे है।

देवगढ ग्राम पंचायत के मनरेगा योजना से लाभान्वित कृषक लगभग औसतन 50 लाख रू. से भी अधिक की संतरें उपज विक्रय कर देते है, पूर्व में कृषक मक्का अथवा गेंहूँ की फसल ही ले पाते थे, जिससे उनकी आय कम होती थी। परन्तु नन्दन फलोद्यान लगने के पश्चात उनकी आय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। किसान अब संतरें के बगीचों में संतरें की उपज के साथ ही अन्य फसल जैसे मिर्ची, मुंग, बरबटी इत्यादि की उपज लेकर, अतिरिक्त आय अर्जित करने लगे है। देवगढ़ ग्राम पंचायत के कृषकों की आय में वृद्धि से प्रेरित होकर अन्य ग्रामों के कृषक भी नन्दन फलोद्यान से लाभान्वित होने हेतु अग्रसर हो रहे है। जनपद पंचायत मोहखेड में ग्राम पंचायत मैनीखापा, हीरावाडी, चूडाबोह, डोडिया, गोविन्दवाडी आदि ग्राम पंचायतों को संतरे के कलस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

कृषक अन्तराम पिता बिरू, निवासी ग्राम देवगढ़ का कहना है कि – मुझें रोजगार गांरटी योजना से अपने खेत में सिंचाई हेतु कपिलधारा योजना का लाभ दिया जाकर, खेत में मेढ बंधान करायी गयी उसके पश्चात नन्दन फलोद्यान योजना से 280 संतरें के पौधें रोपित किया, मजदूरी की समग्र राशि का भुगतान योजना से किया गया। प्रतिवर्ष मुझे

बगीचें से 2 से 3 लाख रू. की आय अर्जित होती है । इसके पूर्व मैं अपने खेत से रू. 40 से 50 हजार की आय ही ले पाता था।

कृषक डीबू पिता विपतलाल निवासी ग्राम देवगढ का कहना है कि – मुझे मनरेगा योजना से 2 वर्ष पूर्व 400 संतरें के पौधें निशुल्क प्रदान किये गये थे, उक्त पौधों को रोपित करने एवं उसकी देखरेख हेतु मजदूरी की राशि, मुझे जनपद से प्राप्त हो जाती है। अन्य किसानों के भांति 3 वर्ष पश्चात मुझे भी मेरे संतरे के बगीचे से 3 से 4 लाख रू. की आय होगी।

ग्राम पंचायत देवगढ़ में मनरेगा योजना से निशुल्क संतरे के बगीचें तैयार कर दिये गये है। जिन्हें अपने बगीचें को तैयार करने हेतु रोजगार प्रदाय कर, मनरेगा से मजदूरी भुगतान की गयी है। ग्राम पंचायत में औसतन प्रति वर्ष, 50 लाख रू. से भी अधिक का संतरा कृषकों द्वारा बेचा जाता है, जिसे महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है।

शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के परिपालन में मनरेगा योजना से जनपद पंचायत मोहखेड की ग्राम पंचायत देवगढ, मैनीखापा, हीरावाडी, डोडिया, गोविन्दवाडी आदि अन्य ग्राम पंचायतों में नन्दन फलोद्यान योजना से संतरे, आम एवं कटहल के पौधों से बगीचा विकसित कर, हितग्राहियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर, आय में वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे है।

रविन्द्र पाल
प्रोग्रामर

जेन्डर (मानसिकता है क्योकि)

"मानसिकता" है क्योकि,
कुण्ठा ऐसी पनपी।

क्षीण करदी शक्ति
क्या कीमत रखती।

ओ मानव हेवान
ये क्यूं परेशान।

वो भी शरीरधारी
क्या दी बराबरी।

स्वार्थ में किया अलग
हुआ न सिद्व सही ठग।

वो कब पायेगे आसन
है एक जटिल प्रशन।

छोडो झूठा अभिमान
दे इन्हे आत्म सम्मान।

हे मालिक इस भांति सजा दो
इन मर्दो को नारी बना दो।

नारी बन जब स्वयं भोगेंगे
तभी नारी पीडा समझेगे।

बिन बैशाखी बन
कर्तव्य पथ चिन्हांकित करने दो।

धरा पर रहा गर्व सदा नारी का
ये हक उसका उसको मिलने दो।

राजेन्द्र प्रसाद खरे, संकाय सदस्य

कोविड–19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

सूचना प्रौद्योगिकी को विगत दशक की सबसे प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में माना जाता है और देश–प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना के कारण जब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा उस समय भी मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं रुका क्योंकि आईटी का प्रयोग कर संचालित किया गया। ऐसे समय जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुए मध्यप्रदेश में एक बड़ी आबादी घरों में सिमट गई है। आम जन–जीवन को सुगम बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार अपने तकनीकी संसाधनों द्वारा लगातार प्रयासरत है।

कोरोना के कारण जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर शेष सारे सरकारी दफ्तर बंद हो गए, यहाँ तक कि मंत्रालय भी। ऐसे में आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं तेजी से लागू करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी। सूचना प्रौद्योगिकी ने जिस तरह बहुआयामी भूमिका निभाते हुए मध्यप्रदेश के लोगों को कोरोना के खिलाफ युद्ध में एकजुट किया, वह काबिले तारीफ है। प्रदेश के सभी वर्गों तक कोरोना से संबंधित आवश्यक जानकारी पहुँचाने, उन्हें जागरूक करने, उन तक आवश्यक मदद पहुंचाने, प्रशासकीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने, आवश्यक निर्णय लेने के लिए दूरस्थ अधिकारियों से बैठक करने, स्वास्थ्य, राशन, दवाइयों की उपलब्धता तथा अन्य जानकारी अद्यतन करने, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सामग्री का लेखा–जोख रखने, विशेषज्ञों से चर्चा करने, गरीब परिवारों तक राशन तथा नगद राशि के भुगतान संबंधी कार्यों में कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने मदद की तथा मध्यप्रदेश शासन ने इसे बेहतर ढंग से उपयोग किया।

कोरोना से इस जंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य विभाग की थी। प्रदेश के बड़े शहरो से लेकर छोटे सूदूर जिलों तथा तहसील स्तर तक के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने, बिस्तरों को आरक्षित करने, वेंटिलेटर की स्थिति को आंकनें, दवाइयों की उपलब्धता, आक्सीजन सिलेडरों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित व्यक्तियों का प्रशिक्षण इत्यादि संभी कार्यों में आईटी सेवाओं की मदद ली गई तथा डाटाबेस को व्यवस्थित किया गया ताकि आवश्यकता होने पर तत्काल मदद दी जा सके। कोरोना से मध्यप्रदेश की जंग में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं जैसे जूम, स्काइप आदि का प्रयोग कर दूर गांवों के स्वास्थ्य अमले को कोरोना के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग कर स्वास्थ्य अमले को कोरोना से जंग में मदद के लिये विस्तृत मार्गदर्शिका भी तैयार की गई

है।

नेशनल इंफार्मेटिक्स सेन्टर (NIC) की वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर हर जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की ठोस रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेंजमेंट ग्रुप काम कर रहे हैं। ये ग्रुप दूरस्थ बैठे अपने अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रोज बैठक कर अगले 24 घंटे की पुख्ता रणनीति बनाते हैं।

कोरोना के संदिग्धों की तलाश करना और उन तक पहुंचना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। विदेश या अन्य प्रदेशों से आने वालों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने के साथ ही उनके सेहत की पड़ताल बहुत अहम है। ऐसे में 'कोविड–19 एक्टिव सर्विलांस टीम की भूमिका बेहद खास है। इस टीम में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई कुशल कम्प्यूटर आपरेटर लगे हैं। इस टीम ने शुरुआती दिनों में ही दिन–रात मेहनत कर विदेश व बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को चिह्नित किया। टीम के कार्य का मुख्य फोकस यही है कि प्रदेश में कोई भी कोरोना के सम्भावित मरीज छूटे नहीं।

COVID पोर्टल हर जिले को सर्वेक्षण डाटा का एक्सेस उपलब्ध कराता है और जिसे राज्य स्तर पर ट्रेक किया जा सकता है।

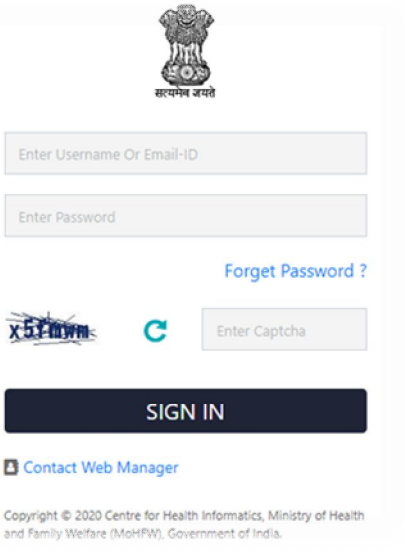

आई.टी सेवाओं के कारण ही राज्य के गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें एक माह का राशन निरूशुल्क दिया गया। ऑन लाइन बैंकिग प्रमालियों का उपयोग कर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातोंमें 88 करोड़ 50 लाख 89 हजार रुपये की आपदा

राशि ट्रांसफर की गई। इससे 8 लाख 85 हजार 89 श्रमिकों को एक–एक हजार रुपये मिले। शासकीयध्अशासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 12वीं तक के 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 430 करोड़ रुपये विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। समेकित छात्रवृत्ति योजना में 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में 430 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई। मध्यान्ह भोजन वितरण में 66 लाख 27 हजार विद्यार्थियों के लिये 117 करोड़ रुपये की राशि उनके अभिभावकों के खातों में डाल दी गई। प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को 148 रुपये प्रति विद्यार्थी और माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को 221 रुपये प्रति विद्यार्थी के मान से राशि दी गई। मध्यान्ह भोजन योजना के 2 लाख 10 हजार 154 रसोइयों कोमानदेय की कुल राशि 42 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपये प्रति रसोइयाँ 2000 रुपयेके मान से उनके खातों में जमा कराई गई।

कोरोना महामारी के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में बन्द हो गये स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों के वेतन का भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग प्रणलियों का उपयोग कर अप्रैल माह तक कर दिया गया है।इसी तरह कुपोषण से मुक्ति के लिये आहार अनुदान योजना में प्रति माह 1000 रुपये के मान से दो माह का अग्रिम भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के द्वारा COVID-19 से सबंधित मानसिक और भावनात्मक समस्याओं पर चिकित्सीय सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श, सायकोएजुकेशन और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड हेतु ऑनलाइन तथा टेलीफोन के माध्यम से हेल्पलाइन सेवा प्रदान कराई जा रही हैं इसके अंतर्गत

होम और फैसिलिटीज क्वारन्टीन किये लोगों तथा आम लोगों को भी कोरोना स्ट्रेस पर मानसिक परामर्श प्रदान कराया जा रहा है। टोल फ्री नम्बर 18002330175 पर लोग 24x7 फोन करके सलाह व परामर्श ले रहे हैं। प्रोएक्टिव कॉल भी किये जा रहे है। कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में अधिक जानकारी

देने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपनी वेब साईट http://www-health-mp-gov-in को अद्यत किया है। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के कारण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नम्बर 104/181 में कॉल रिसीव किये जा रहे है, इस कॉल सेन्टर में विगत एक माह में सूचनाएं प्रदान करने, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारें में परामर्श तथा शिकायतों से संबंधित 96 हजार से ज्यादा टेलीफोन कॉल पर उनका समाधान दिया गया है।

भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी एकीकृत इंटीग्रेटेड कंट्रोलएण्ड कमाण्ड सेंटर जिससे मध्यप्रदेश के 7 शहर भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, एवं सतना जुड़े है में इन शहरों में लगे सभी सेंसर्स जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में लगे जीपीएससेन्सर्स, डायल 100 वाहन की स्थिति, 108 एम्बुलेंस की स्थिति, स्मार्ट पोलएवं स्मार्ट लाइटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैमरे, स्मार्ट मैप इत्यादि व्यवस्थाओं को रियल टाईम में देखा जा रहा है तथा इस एकीकृत कण्ट्रोल एंड कमांड सेंटर से आपातकालीन स्थिति एवं आपदा प्रबंधन में तुरंत कार्यवाही करने हतु निर्देश प्रदान किए जा रहे है। इन शहरों में कोई भी आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष से लाइव विडियो देखकर जरूरी सेवाओं जैसे फायरबिग्रेड, डायल 100 एवं 108 एम्बुलेंस को तुरंत सूचित किया जाने की व्यवस्था है। आपदा की घड़ी में देश मास्क जैसी मामूली चीजे भी अन्य देशो सें आयात करवा रहा है और इसमें भी बहुत समय लग रहा है। साथ ही क्वालिटी के मामले में भी यह मास्क खरे नहीं उतर रहे हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश ने लॉकडाउन के ऐसे वातावरण में महिलाओं को रोजगार देने और नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा जीवन शक्ति योजना (Madhya Pradesh Mask Scheme) की शुरूआत की है। इस योजना से जो शहरी महिलाएं काम न होने की वजह से घर पर खाली बैठी थी, वह अब इस दौरान भी अच्छी आय अर्जित कर पाएंगी। योजना में सरकार महिलाओं को मास्क बनाने का काम सौंप रही है। इसके बाद सरकार महिलाओं से 11 रूपए प्रति मास्क खरीद कर जनता तक पंहुचाने का काम करेगी।यह कार्य डी पूर्णत विभाग की वेवसाइट http://maskupmp-mp-gov-in के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर मास्क निर्माण के लिये 25 अप्रैल से जीवन शक्ति योजना लागू की गयी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर योजना के क्रियान्वयन के पहले दिन प्रदेश में 4200 शहरी महिलाओं ने अपना पंजीयन कराया है।

कोरोना के संदर्भ में केन्द्र शासन द्वारा जारी मोबाइल एप्प आरोग्यसेतु के साथ साथसीएम हेल्पलाइन 181, टेलीमेडिसिन, सर्व ग्वालियर एप्प, सार्थक एप (खण्डवा और सागर) जैसे कई नवाचारी प्रयास उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।मध्यप्रदेश शासन के जनसम्पर्क विभाग ने फेसबुक के सहयोग से एमपी गव्हर्नमेंट कोरोना व्हाट्सएप इन्फोडेक और विभाग का आधिकारिक फेसबुक मैसेंजर श्चौटबॉटश तैयारकराया है। जन सामान्य को कोरोना व्हाट्सएप हेल्प डेस्क (917834980000) और मैसेंजर चौटबॉट पर आसानी से कोरोना वायरस संक्रमण

से जुड़ी जानकारी मिल रही है।लॉकडाउन के दौरान ग्वालियर नगर में रोजमर्रा की वस्तुएँ उपलब्ध कराने में श्सर्व ग्वालियर एपश अहम भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों की लॉकडाउन अवधि में छात्रों का नुकसान न हो इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे है। शडिजी लैप – आपके घर योजना के माध्यम से 12वीं तक के विद्यार्थी अंग्रेजी, हिन्दी, गणित औरविज्ञान आदि विषयों की अध्ययन सामग्री व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश शासन ने भोपाल में कोरोना के संदर्भ में एकराज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का निर्माण किया है। इस कंट्रोल कक्ष में 450 प्रशिक्षित कर्मचारियों को पदस्थ किया गया।यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन भोपाल के इंटीग्रेडेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नागरिकों एवं प्रवासियों की विभिन्न समस्याओं को प्राप्त कर संबंधितों के पास निराकरण के लिये भेज रहा है। कोरोना की इस लड़ाई में न सिर्फ शासकीय अमले में शामिल लोग शामिल हैं वरन सेवाभाव रखने वाले कई सामाजिक संगठन भी इस लड़ाई में शासन के साथ है। इन संगठनों के साथ दिए बिना इतने बड़े प्रदेश में हर स्तर पर लोगों को आवश्यक सुविधाएं पहुँचा पाना असंभव था। इसके लिए भी आई टी सेवाओं की मदद ली गई। लोगों को कोरोना से संघर्ष के लिये तैयार करने के लिये श्वालिंटियर बनो–सेवा करोश की भावना से प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान राहत कार्यों में अपना योगदान देने के इच्छुक लोग https://mapit.gov.in/COVID-19/Login.asp वेबसाइट पर पंजीयन करवा सकते हैं। इस योजना में अभी तक कुल 63087 लोग जुड़कर अपनी सेवाएं लोगों तक पहुँचा रहे है।

ऐसे समय में जब एक और हम इस महामारी में मनुष्य ओ प्रत्येक स्तर पर प्रभावित किया है , वही दुसरी और सूचना प्रोधोगिकी का उपयोग जीवन को महामारी से बचते हुए सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । ऐसे ही कुछ उदाहरण निम्न है

- विधार्थी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे है
- ऑनलाइन माध्यम से सामग्री क्रय की जा रहे है
- ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श
- ऑनलाइन दवाईया क्रय करना
- ऑनलाइन माध्यम से बिभिन्न आवेदन करना
- ऑनलाइन बैंकिंग आदि

शिव कुमार सिंह,
प्रोग्रामर

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से ''सच हुआ सपना, अपने आशियाने का''

मध्यप्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की जनपद पंचायत गरोठ की ग्राम पंचायत ढाबला गुर्जर के हितग्राही जगदीश पिता गोकुल विश्वकर्मा अपने परिवार जिसमें उसकी तीन बेटियाँ सहित जीवन यापन करता है। कठिनाईयों भरा जीवन आमदनी इतनी कि दो वक्त की गुजर बसर हो जाती थी, रहने के लिए पुराना टपरेल का मकान जिसमें शुद्ध हवा व प्रकाश का अभाव निरंतर रहता था तथा वर्षा के मौसम में आंधी–तूफान, बारिश से अतिरिक्त खार्चा व परेशानियां खड़ी हो जाती सो अलग, ऐसे में कम आमदनी बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा–दीक्षा, बीमारियों में खर्च के कारण जगदीश विश्वकर्मा इतनी जमापूंजी भी इकठ्ठी नही कर पा रहा था कि कम से कम अपने बच्चों के लिए पक्का मकान ही बना ले, किन्तु बचत के नाम पर हमेशा खाली हाथ। ऐसे में उसके बच्चों व परिवार का जीवनस्तर काफी निम्नस्तर का हो चला था।

एस.ई.सी.सी. 2011 सर्वे की अन्य पिछडा वर्ग की सूची से शासन लक्ष्य अनुसार प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति के साथ जगदीश विश्वकर्मा ने अपने कच्चे मकान को गिराकर विभिन्न स्तरों पर राशि प्राप्त होने से पक्के आवास का निर्माण कराया गया। आवास में शुद्ध हवा का आवागमन, स्टेण्ड वाला किचन, अलग से शौचालय शासन द्वारा स्वीकृत डिजाईन अनुसार निर्मित किया गया जिसमें परिवार के स्वास्थ्य व जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ। बीमारियों पर होने वाला अतिरिक्त खर्च बचने लगा जिससे पत्नी व बेटियों ने सिलाई का कार्य सीखकर अतिरिक्त आय का साधन विकसित कर लिया सिलाई–कढ़ाई से घरेलू आमदनी बढ़ी साथ ही हितग्राही जगदीश भी बचत की राशि से फर्नीचर बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर फर्नीचर कार्य प्रारंभ कर पारिवारिक आय की वृद्धि में पूर्ण सहयोग देने लगा। इस आय वृद्धि से हितग्राही के परिवार के जीवन स्तर में काफी सुधार आया तथा हितग्राही की पुत्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने की और अग्रसर है एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

इस प्रकार एक ग्रामीण गरीब परिवार के मुखिया श्री जगदीश प्रधानमंत्री आवास–ग्रामीण योजना अंतर्गत लाभांवित होकर परिवार सहित खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे है जो उनके लिए किसी सपने से कम नही है।

शशांक भार्गव,
संकाय सदस्य

समूह ने संभाली गेहूं उपार्जन की कमान

विश्व में अब हर जगह अलग–अलग तरीके से लॉकडाउन हटाकर बाजार, व्यवसाय, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी कोरोना से पूरी तरह ठीक करने वाली दवा नहीं आई है, सिर्फ वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ऐसे में सभी को यही सलाह दी जा रही है कि मास्क और सेनिटाइजर के इस्तेमाल में कोई ढील न बरती जाए। मास्क का सही इस्तेमाल नये व्यक्ति में संक्रमण को लगभग 95 प्रतिशत तक रोक लेता है। लम्बे समय तक कोरोना संक्रमण के चलते अब देखने में आ रहा है कि लोग मास्क पहनने में लापरवाही बरतने लगे हैं। यही कारण है कि जो लोग पहले तो पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे थे वे भी संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं।

राजगढ़ के चाटूखेड़ा ग्राम में इस बार समूह के माध्यम से सरकारी गेहूं की खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा इस बार गेहूं उपार्जन केंद्र में समूह को अवसर दिया गया है। इसी के तहत राजगढ़ के चाटूखेड़ा ग्राम में अंबिका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गेहूं उपार्जन में लगी हुई हैं।

जिला उपार्जन समिति के चयन के आधार पर आजीविका मिशन से जुड़े अंबिका स्वयं सहायता समूह को 7 ग्रामों की खरीदी का दायित्व सौंपा गया है। यह

समूह 571 किसानों के गेहूं का उपार्जन करेगा। समूह द्वारा अब तक 483 किसानों से 22514 क्विंटल गेहूं की खरीदी की है। शासन की मंशा महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की रही है। इन प्रयासों से महिलाओं को समाज में निर्णायक भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा गेहूं उपार्जन केंद्र का संचालन करना, इसी भावना की अभिव्यक्ति है। जिला प्रशासन द्वारा सौपे गए कार्य के तहत समूह की महिलाएं भी उत्साहित होकर कार्य कर रही हैं। समूह द्वारा स्थापित केंद्र का निरीक्षण लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए जा रहे हैं। समूह द्वारा हासिल उपलब्धि के बाद अगले सीजन में ज्यादा से ज्यादा समूहों को उपार्जन से जोड़ा जाएगा।

समूह की श्रीमती पवित्रा बाई बताती हैं कि काम चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सभी के सहयोग से काम करने में मजा आ रहा है। श्रीमती पवित्रा का कहना है कि हमारी सफलता के बाद अन्य समूह के लिए भी इस कार्य हेतु रास्ते खुलेंगे।

रूषाली पोरस,
मु.का.अ.ज.पं.

''कोविड–19 से बचाव हेतु देवकृपा समूह का अभिनव प्रयास''

म.प्र. डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के विकासखंड नलखेडा जिला आगर मालवा के ग्राम पचलाना के देवकृपा स्व–सहायता समूह की दीदियों द्वारा कोविड–19 महामारी में अभिनव प्रयास किया गया। जहाँ लोग महामारी से बचाव के लिए अपने–अपने घरों में बंद थे वहीं देवकृपा समूह की महिलाओं द्वारा कोविड–19 से बचाव हेतु गांव में प्रचार–प्रसार किया, ग्राम पंचायत के साथ पंचायत क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर अपना सहयोग किया।

समूह की महिलाएँ पूर्व से सिलाई कार्य में निपुण होने से समूह द्वारा कोविड–19 काल में महामारी से लड़ाई व रोकथाम व बचाव हेतु मास्क निर्माण का कार्य किया गया सभी महिलाओं की आपसी सहमति से अपने समूह फण्ड़ राशि का उपयोग माँ लक्ष्मी सी.एल.एस. पचलाना को 3000 मास्क एवं माँ बगलामुखी सी.एल.एस. को 5000 मास्क निशुल्क उपलब्ध कराये गये है, साथ ही जनपद पंचायत नलखेडा को 10000 मास्क सशुल्क बनाकर सप्लाय किये गये।

जनपद पंचायत द्वारा प्रति मास्क 10/– रू. के मान से भुगतान किया गया जो कोविड–19 के दौरान समूह की महिला को स्वरोजगार भी मिला। इस प्रकार देवकृपा समूह द्वारा कोविड–19 काल में कुल 18000 मास्क बनाकर वितरण कार्य किया गया। सी. आई.एफ. को प्रदाय किये मास्कों को विकासखंड नलखेडा के ग्राम संगठन के प्रत्येक ग्राम के 200 के मान से कुल 40 ग्राम संगठन को मास्क वितरण किया गया जो कोविड–19 से बचाव हेतु मास्क ही दवा की भूमिका में होने से महामारी को रोकने में कहीं न कहीं देवकृपा समूह का अभिनव योगदान रहा है।

अरविंद सोनगरे
संकाय सदस्य

''कपिलधारा'' से आर्थिक समृद्धी कि ओर

सुरपालसिंह पिता मजीद निवासी ग्राम बडीफाटा ग्राम पंचायत बेहडवा जनपद पंचायत चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर (म.प्र.) के निवासी होकर मनरेगा योजना अन्तर्गत इन्हें कपीलधारा कूप वर्ष 2018–19 में प्राप्त हुआ था जिसकी लागत 2.10 लाख स्वीकृत हुई थी हितग्राही अ.ज.जा के होकर इनके पास कुल 2 हेक्टेयर भूमी है, इनके पास कृषि भूमी के अलावा आजीविका हेतू अन्य कोई साधन नहीं था जिससे ये गरीबी में अपने परिवार के साथ बडी ही कठीनाई से जीवन यापन कर रहे थे । इनके पास सिंचीत भूमि नहीं होने से सालभर में केवल बारीश की फसल ही ले पाते थे जिससे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था जीवन यापन हेतु इन्हें परिवार के साथ मजबूरी वश मजदूरी करना पड रही थी इसके बावजूद भी आर्थिक तंगी से बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी । इनका जब शासन की मनरेगा योजना में कपिलधारा कूप स्वीकृत हुआ तो इन्हें बड़ी खुशी हुई कूप की खुदाई पूर्ण होने के पश्चात जब कुंए में पानी निकला तो इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा अब ये पम्प से सिंचाई कर रबी एवं खरीब दोनों प्रकार की फसल लेने लगे साथ ही गर्मियों में सब्जियां उगाकर भी फसल लेने लगे हैं, जिससे उन्हें रोज नगद आमदनी हो रही है। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो जाती है, इस प्रकार सुरपालसिंह की जिन्दगी में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से बदलाव आने लगा अब इन्हें मजदूरी करने भी नहीं जाना पड़ता, घर का रहन सहन भी बदला है, बच्चों को शिक्षा भी अच्छे से दे पा रहे हैं। शासन की इस योजना से उनके जीवन में बदलाव आया है एवं पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है।

प्रकाश पुरकर
संकाय सदस्य